

सोनम वांगचुक समेत 20 समर्थक हिरासत में, लद्दाख भवन के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके 20 समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वे लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है लेकिन उनके आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रविवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) और 20 अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वह लद्दाख भवन (Laddakh Bhawan) के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि वे प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि शांतिपूर्वक बैठे थे।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमित देने पर विचार

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि

प्रदर्शनकारियों को लद्दाख भवन के बाहर बैठने की कोई अनुमति नहीं है। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आवेदन किया है। उनके आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

उन्हें किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

30 सितंबर को पहुंचे दिल्ली

सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों के साथ लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह से दिल्ली तक मार्च किया। वह 30 सितंबर को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस ने राजधानी के सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में लिया था। उन्हें 2 अक्टूबर की रात रिहा कर दिया था।

सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की मांग कर रहे हैं।

संविधान की छठी सूची में क्या?

संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। यह स्वायत्त परिषदों की स्थापना करता है

लेह से दिल्ली तक मार्च का आयोजन लेह एपेक्स बाडी (एलएबी) द्वारा किया गया, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ पिछले चार वर्षों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने

की मांग कर रहा है।

लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग की मांग।

लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग

लोकसभा सीट बनाने की मांग।

साथ ही जल्द भर्ती प्रक्रिया और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है।

जिनके पास इन क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होती हैं।

क्या हैं मांगें



'ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज कायम करना चाहते हैं', बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले केजरीवाल

मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लोगों से बीजेपी के खिलाफ साथ आने की अपील की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल करते हुए कहा कि ऐसा क्या हुआ है कि दिल्ली और मुंबई में इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं?

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की संरे आम गोली मारकर हत्या ने देशभर में दहशत फैला दी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता से बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की अपील की है।

क्यों एक्टिव हो गए इतने सारे गैंगस्टर?

इसी क्रम में दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, रं मुंबई में भाजपा की सरकार है और आप कानून व्यवस्था की स्थिति देख सकते हैं, उनके नेता की हत्या कर दी गई है। दिल्ली में भी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है और यहां भी हालात मुंबई जैसे होते जा रहे हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अपना सारा समय राजनीति में बिताती हैं, उनके पास शासन के लिए समय नहीं है। हमें नहीं पता कि कार्रवाई होगी या नहीं,



लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि दिल्ली और मुंबई में इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं, क्या सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है? यह बहुत गंभीर स्थिति है।"

जांच में मुंबई पुलिस को सेल कर रही मदद

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई पुलिस को मदद करने मुंबई जा सकती है। स्पेशल सेल सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। शनिवार की रात बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने उन्हें रोककर उनपर ताबड़तोड़ छह गोलियां चला दी थी।

घायल बाबा सिद्दीकी को उपचार के लिए तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया

सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल के पांच सदस्यों टीम मुंबई पुलिस को जांच में मदद करने मुंबई जा सकती है। सेल को शक है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे गैंगस्टरों के आपसी वर्चस्व हो सकता है।

मुंबई व दिल्ली पुलिस इसे मुंबई में व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता व झगुगी पुनर्वास परियोजना आदि कई पहलुओं पर भी जांच कर रही है। हत्या आरोपित जिन दो बदमाशों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उनमें हरियाणा का रहने वाला गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश का धर्मराज राजेश कश्यप है।

लॉरेंस गिरोह ने ली हत्या कराने की जिम्मेदारी

पुलिस को मौके ने नाइन एमएम के कुछ खोखे मिले हैं। वारदात के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया के जरिये महाराष्ट्र के शुबू लोनकर ने लॉरेंस गिरोह द्वारा हत्या कराने की जिम्मेदारी ली है। उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। इस मामले में मुंबई व दिल्ली पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस से पूछताछ करने जेल जा सकती है।

'प्रधानमंत्री द्वारा आवंटित फ्लैटों को ब्लैक में बेचा जा रहा', आप के आरोप पर मचा सियासी घमासान



आप नेता व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गीवासियों को मिलने वाले फ्लैटों में घोटाले का आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जिन फ्लैटों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उन्हें ब्लैक में बेचा जा रहा है। भाजपा ने इन आरोपों को बेवुनियाद बताया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि दिल्ली में गरीब झुग्गी निवासियों को झुग्गी के बदले पक्का मकान देने की जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को झुग्गी के बदले पक्का मकान दिया जाता है, ताकि वह लोग और उनके बच्चे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें और साथ ही साथ दिल्ली में झुग्गियों की संख्या को

काम किया जा सके।

आप ने कहा है कि इसी श्रृंखला में अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कालकाजी में स्थित ऐसे ही फ्लैटों का उद्घाटन किया था, जो कि झुग्गी में रहने वाले व्यक्तियों को झुग्गी के बदले मिलने थे।

सौरभ भारद्वाज ने की मामले की जांच की मांग

आप ने आरोप लगाया है कि एक स्टिंग ऑपरेशन में बात साफ हो रही है कि जिन फ्लैटों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को आवंटित करने के लिए किया था, उन फ्लैटों को एक बड़े भ्रष्टाचार के तहत ब्लैक में उन लोगों को बेचा जा रहा है जो लोग झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग नहीं हैं। आप नेता व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी जांच की मांग की है।

दिल्ली सरकार बताए कितने गरीबों को आवास मिला: सचदेवा

सौरभ भारद्वाज के आरोप पर

भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार के मंत्री केंद्रीय एजेंसियां के विरुद्ध भ्रम फैलाने बहाने का काम करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भी आवास आवंटन को लेकर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

इस तरह के भ्रामक आरोप लगाने की जगह मंत्री को बताना चाहिए कि पूर्वी की शीला दीक्षित सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए नरैला एवं बवाना में बनाए गए 40 हजार फ्लैट का आवंटन अब तक क्यों नहीं किया गया?

उन्होंने कहा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का काम गरीबों को घर उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में कितने गरीबों को घर दिए गए? दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने का भी कारण बताना चाहिए।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद (ईसी) में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि को शामिल करने का फोरम ने विरोध जताया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। फोरमऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस (शिक्षक संगठन) ने बताया है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक संकुलन जारी कर अपने अधीन आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद (ईसी) में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। संकुलन में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने अपने अधीन आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की है और इन संस्थानों की कार्यकारी परिषद (ईसी) में मंत्रालय के प्रतिनिधित्व में असमानता देखी है। 148 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 20 पहले ही अपने कार्यकारी परिषदों में मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल कर लिया है। जबकि 28 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वर्तमान में ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संकुलन में यह भी लिखा है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि (उच्च शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को आपके विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए ।बता दें कि सोमवार (14 अक्टूबर) को डीयू की कार्यकारी परिषद (ईसी) की मीटिंग हो रही है



जिसमें शिक्षा मंत्रालय के पत्र को रखा जाना है।

फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संकुलन का कड़े शब्दों में विरोध किया है और कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के निर्णय लेने वाले निकाय जैसे कार्यकारी परिषद (ईसी) से संबंधित मंत्रालय से सरकार या नौकरशाही का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सीधा हमला बताया है। विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा व कुलपति की शक्तियों को कमजोर किया जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिनिधि सरकार की भाषा बोलेंगे और मनमानी करके अपना एजेंडा लागू करेंगे। उन्होंने बताया है कि डीयूएफ 1922 में बना था जो कि उसे

पूरी स्वायत्तता देता है जबकि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में बने हैं, उन पर सरकार अपना एजेंडा लागू कर सकती है क्योंकि उन विश्वविद्यालयों की प्रकृति हमारे विश्वविद्यालय से भिन्न है। यदि यहाँ पर सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होगा तो नियुक्ति, पदोन्नति तथा सभी संसाधनों पर सरकार का कब्जा होगा इसलिए इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। डॉ. सुमन ने बताया है कि दिल्ली सरकार से शत प्रतिशत वित्त पोषित 12 कॉलेजों में इनके नुमाइंदों को गर्वर्निंग बॉडी में रखा जाता है जहाँ वे अपनी मनमानी करते हैं, इसीलिए पिछले दो साल से सरकार की गर्वर्निंग बॉडी न होने से शिक्षकों का समय पर वेतन नहीं मिलता, अभी तक एडवॉक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई, कर्मचारियों

की स्थायी नियुक्ति भी पिछले एक दशक से नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा मंत्रालय के सदस्यों द्वारा सरकार की नीतियों को लागू करेंगे तो शिक्षकों के अंदर डर पैदा होगा इसलिए डीयू की स्वायत्तता को इसी तरह बरकरार रखा जाए।

डॉ. हंसराज सुमन का यह भी कहना है कि भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) का सदस्य बनाने से डीयू में दूसरा पावर सेंटर बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, इससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्त स्थिति के लिए घातक है। उन्होंने डीयू का उदाहरण देते हुए बताया कि डीयू अधिनियम और ईसी संरचना को परिभाषित करते हैं कि सचिव और उच्च शिक्षा, भारत सरकार को शामिल करने की अनुमति नहीं देते। डीयू ईसी में पहले से ही विजिटर और चॉंसलर नामित है जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बताया है कि सचिव, उच्च शिक्षा और सचिव यूजीसी या उनके नामित व्यक्ति डीयू की वित्त समिति में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह से केंद्र सरकार के तीन सांसदों को यूनिवर्सिटी कोर्ट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने सोमवार को हो रही ईसी की मीटिंग में इस तरह के संकुलन का विरोध किये जाने की सदस्यों से मांग की है।

भारतीय कैंसर संस्थान (आईसीआई) लोगों को जीके1, दिल्ली में स्थित अपने अभूतपूर्व अस्पताल में आमंत्रित करता है

सुषमा रानी

नई दिल्ली। भारतीय कैंसर संस्थान ने आज दिल्ली में अपने अनुसंधान और उपचार अस्पताल के उद्घाटन की घोषणा की। आईसीआई में, मरीज कोमोथेरेपी और सर्जरी दोनों के साथ-साथ टारगेट थेरेपी और इम्प्यूनोथेरेपी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। रोगियों में उन्नत कैंसर चरण के मामलों में भी उपचार के विकल्पों पर विचार किया जाता है।

आईसीआई का निर्माण विविध डॉक्टरों और ऑन्कोलॉजिस्ट की मजबूत नींव पर किया गया है जो उच्चतम स्तर की देखभाल और सहानुभूति के साथ रोगियों का इलाज करते हैं। विशाल अनुभव के साथ, वे पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ जरूरतमंद लोगों को दयालु देखभाल प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

दिल्ली और पूरे भारत में सही इलाज की तलाश करने वाला कोई



भी व्यक्ति सही देखभाल के लिए आईसीआई का दौरा कर सकता है। उपचार में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए जीके1 के अस्पताल में पहले से ही कई लोग आ रहे हैं।

आईसीआई के साझेदारों में से एक, लोकप्रिय गायक मीका सिंह ने भी अपने एनजीओ 'डिवाइन टच' और आईसीआई के बीच एक करीबी कामकाजी सहयोग विकसित किया है। उन्होंने और आईसीआई के संस्थापक सदस्य डॉ. तरंग कृष्णा दोनों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि

वे जरूरतमंद लोगों के लिए 'परिवर्तन' के बड़े कारण में योगदान देना जारी रखेंगे। हमारे मुख्य अतिथि - प्रसिद्ध बॉलीवुड सैलिब्रिटी - सुनील शेठ्ठी ने अपनी उपस्थिति से इस उद्घाटन को सफल बनाया।

आईसीआई उन अस्पतालों में से एक है जिसका एजेंडा समुदाय को कैंसर से बचना है, और यही कारण है कि वे कैंसर का पता लगाने के लिए हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से मुफ्त परीक्षण की पेशकश कर रहे हैं।

'जमानत देने से रोकना सजा के समान', दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोपी SI को बेल देते हुए की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी सब-इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह यादव को जमानत देते हुए कहा कि किसी आरोपी को मामले के गुण-दोष के आधार पर रिहा करना उचित समझने के बावजूद जमानत नहीं देना सजा के समान है। कोर्ट ने कहा कि मामले में सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है।

नई दिल्ली। रिश्वत लेने के मामले में आरोपी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को नियमित जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि निसंदेह

आरोपी युद्धवीर सिंह यादव पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है, लेकिन अदालत की राय है कि किसी आरोपी को मामले के गुण-दोष के आधार पर रिहा करना उचित समझने के बावजूद जमानत नहीं देना सजा के समान है। पीठ ने कहा कि मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है।

पीठ ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता के उस पत्र तर्क की, जिसमें उसने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को सुनाए गए निर्णय में जमानत के योग्य मामला होने के बावजूद उसे नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था।

अदालत को अपनाना चाहिए

संवेदनशील दृष्टिकोण

याचिकाकर्ता के जमानत पाने का हकदार होने या नहीं होने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकार की अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अदालतों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे लोक सेवकों में जनता का विश्वास कम हो जाता है, जो कि जनता की रक्षा करने के लिए होते हैं।

कोर्ट ने दी जमानत

अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी



मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता सब इंस्पेक्टर ने नियमित जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसे झूठा फसाया गया है।

जांच में सहयोग किया, फिर भी...

उसने यह भी तर्क दिया कि जांच में उसने पूरा सहयोग किया है और अब हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। वहीं, याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) की नागरिकता के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahbad High Court) में लंबित याचिका

की एक प्रति दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को समय दिया है। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने याचिका की प्रति प्राप्त कर ली है और उस मामले में की गई प्रार्थनाएं उनकी दलीलों से अलग हैं।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेल की पीठ ने सुब्रमण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज दाखिल करने को कहते हुए सुनवाई छह नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

गाजियाबाद और नोएडा वाले ध्यान दें, 20 दिनों तक नहीं मिलेगा पानी; लाखों लोग होंगे प्रभावित

परिवहन विशेष न्यूज

हरिद्वार में गंगनहर की सफाई कार्य के चलते नोएडा और गाजियाबाद में 20 दिनों तक गंगाजल की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे दिवाली तक लगभग 10 लाख की आबादी प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है कि इस अवधि के दौरान निवासियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। ऐसे में सोमवार से लोगों को गंगाजल नहीं मिलेगा।

साहिबाबाद। गंगनहर की सफाई के लिए शनिवार रात 12 बजे हरिद्वार से गंगनहर को बंद कर दिया गया। गंगनहर बंद होने के बाद प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट में एक दिन के लिए रिजर्व गंगाजल खखा जाएगा। जिससे केवल एक दिन यानी रविवार को ही पानी की आपूर्ति की जाएगी।

ऐसे में सोमवार से लोगों को गंगाजल नहीं मिलेगा। नगर निगम और जीडीए द्वारा दिन में केवल एक समय नलकूप और टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाएगी। अब दिवाली तक यानी 20 दिनों तक ट्रांस हिंडन की 10 लाख की आबादी को एक

समय ही पानी मिल सकेगा।

गंगनहर से ही गंगाजल प्लांट में आता है पानी

दशहरे के समय किसानों को पानी की जरूरत कम रहती है। जिस वजह से हर वर्ष इस दौरान गंगनहर की सफाई की जाती है। गंगनहर से ही प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट में गंगाजल आता है। प्रताप विहार प्लांट की भंडारण क्षमता 150 क्यूसेक पानी की है।

गंगनहर बंद होने पर प्लांट में एक दिन का पानी भंडारण करके रखा जाता है। इस प्लांट से वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, डेल्टा कॉलोनी, कौशांबी और सिद्धार्थ विहार को गंगाजल मिलता है। इसके अलावा नलकूप और टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाती है। गंगाजल सुबह और शाम के समय एक-एक घंटे की आपूर्ति की जाती है।

शनिवार रात 12 बजे से बंद की गई गंगनहर

शनिवार रात 12 बजे हरिद्वार से गंगनहर बंद कर दिया गया। सोमवार सुबह से लोगों को गंगाजल की आपूर्ति नहीं होगी। दिन में दो बार की बजाय एक बार ही नगर निगम द्वारा नलकूप से पानी की आपूर्ति की जाएगी।

दिवाली के बाद गंगाजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता ब्रिजराज ने बताया कि 12 अक्टूबर से दो नवंबर तक गंगनहर बंद रहेगी। इस दौरा गंगनहर की सफाई होगी।



पानी के निजी प्लांटों पर रहने पड़ेगा निर्भर

गंगाजल की आपूर्ति बंद होते ही ट्रांस हिंडन क्षेत्र के लोगों को बोतलबंद पानी के भरोसे रहने पड़ेगा। इनके पानी की गुणवत्ता की भी गारंटी नहीं होती है। गंगाजल नहीं मिलने पर मजबूरी में लोगों को इस पानी को ही खरीदना पड़ता है।

शनिवार को जगह-जगह हुई पानी की किल्लत

ट्रांस हिंडन क्षेत्र में शनिवार को भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। इंदिरापुरम, वैशाली, डेल्टा कालोनी, वसुंधरा, कौशांबी के लोगों को पर्याप्त गंगाजल नहीं मिला।

तुलसी निकेतन में गंदे पानी की आपूर्ति हुई। सूर्य नगर, चंद्र नगर, बुज विहार, कौशांबी, श्याम पार्क, लाजपत नगर, भोपुरा, डीएलएफ, इंद्रप्रस्थ आदि क्षेत्र में पानी की किल्लत होने की शिकायतें प्राप्त हुईं।

प्लांट से इस तरह होगी गंगाजल की आपूर्ति

100 क्यूसेक गंगाजल की सप्लाई प्लांट से होती है।

80 क्यूसेक गंगाजल नोएडा को दिया जाता है।

15 क्यूसेक गंगाजल इंदिरापुरम को मिलता है।

05 क्यूसेक की गंगाजल सिद्धार्थ

विहार को मिलता है।

नगर निगम द्वार पानी आपूर्ति के संसाधन

संसाधन : संख्या

5-10 एचपी के पंप : 1050

15-30 एचपी के पंप : 300

हैंडपंप की संख्या : 7000

ओवर हैड टैंक : 51

वाटर टैंकर : 71

रेनीवेल : 03

पानी की मांग और आपूर्ति

कागजों में कुल मांग : 355 एमएलडी

आपूर्ति करने का दावा : 325 एमएलडी

कुल बोरिंग 76

यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग नै कसी कमर, घरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में बिजली चोरी रोकने और गाजियाबाद को बिजली बिल की समस्या से निजात दिलाने के लिए विद्युत निगम ने कमर कस ली है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिससे बिजली चोरी का भी पता चल सकेगा। शुरुआत में विद्युत उपकेंद्रों के फीडर पर स्मार्ट मीटर लगेंगे जिसके बाद ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली चोरी पर लगाम लग सकेगी।

गाजियाबाद। बिजली चोरी को रोकने और बिजली की खपत कम करने व उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से निजात दिलाने को लेकर विद्युत निगम तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली चोरी का भी पता चल सकेगा। शुरुआत में विद्युत उपकेंद्रों के फीडर पर स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिसके बाद ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

जिनमें सरकारी कार्यालय और आवास के बाद उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। गाजियाबाद जिले में करीब चार लाख 25 हजार उपभोक्ताओं के लिए 41 विद्युत उपकेंद्र संचालित हैं। यह इनकमिंग व आउटगोइंग मिलकर 231 फीडर हैं। विद्युत निगम की ओर से विद्युत उपकेंद्र के फीडर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है।

पुलिस ने महापंचायत जाने से रोका, तो NH-9 पर धरने पर बैठ गए विधायक नंदकिशोर गुर्जर; थम गई वाहनों की रफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के विवादित बयान के बाद तनाव खत्म होता नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठनों ने रविवार को डासना देवी मंदिर पर महापंचायत का आयोजन किया लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। पुलिस ने मंदिर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर लोगों को महापंचायत में नहीं जाने दिया। इस बीच लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हाईवे पर धरने पर बैठ गए।

गाजियाबाद। डासना देवी मंदिर पर हिंदुओं की महापंचायत कड़े सुरक्षा प्रबंधन के चलते नहीं हो पाई। पुलिस ने मंदिर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा।

मंदिर जाने की मांग पर अड़े लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हाइवे पर ही पंचायत की। विधायक ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी की जाए। उनकी वजह से हालात बिगड़े हैं।

विधायक ने पंचायत सम्पाप्त होने के बाद बताया कि तीन मांगे सरकार से रखी गई हैं। जिनमें रोहिंया मुस्लिमों को बाहर निकालने, डासना देवी मंदिर पर हमला करने वालों पर रासुलापुर निहार और जिहाद करने वालों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

दूसरी तरफ हापुड़ रोड पर इंपीरियल फार्म हाउस में भाईचारा मंच ने भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। संयोजक नाहर सिंह यादव ने कहा कि मौजूदा समय में समय में जो तनाव है उसे दूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में समाज तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

डासना देवी मंदिर प्रबंधन प्रवक्ता डॉक्टर उदित यादव ने कहा है कि सुबह चार बजे से पुलिस किसी को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही है। सुबह से मंदिर आने वालों को मुख्य द्वार से ही वापस लौटना पड़ा रहा है। उनका आरोप है कि मंदिर आए दो सन्यासियों को

पुलिस उठाकर ले गयी है।

एनएच-नौ पर धम गई वाहनों की रफ्तार

वहीं, डासना देवी मंदिर जाने से रोकने पर नाराज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। इससे एनएच-नौ पर वाहनों की रफ्तार थम गई।

तीन नेताओं ने रची थी डासना देवी मंदिर पर हमले की साजिश, गाजियाबाद पुलिस को मिले खुफिया इन्पुट बता दें कि भीड़ जुटने से रोकने के लिए पुलिस ने डासना देवी मंदिर जाने

वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। किसी को भी मंदिर की तरफ जाने नहीं दिया। मंदिर में कैद करने जा रहे डॉक्टर बीपी त्यागी को पुलिस ने वापस भेज दिया। बीपी त्यागी का कहना है कि वह मंदिर में स्वास्थ्य कैंप लगाने जा रहे थे।

विधायक ने महापंचायत को लेकर बयान जारी किया

इससे पहले शनिवार को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने महापंचायत को लेकर शनिवार को अपना बयान जारी करते हुए कहा कि डासना मंदिर पर ऊपर हुए हमला होना बहुत ही गलत है। मंदिर

की समिति व साधु-संतों के आह्वान पर महापंचायत बुलाई गई है। उसमें पुझे भी बुलाया गया है। इसमें लोनी, गाजियाबाद समेत आसपास के जिलों के लोगों में आक्रोश है।

महंत के बयान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अति प्राचीन मंदिर पर हमला करना गलत है। लोग डीएम के यहां जायन करने गए थे उनके निष्पक्ष हो एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर गंभीर हैं। सरकार को बदामन करने के लिए एक अधिकारी लगातार प्रयास कर रहा है।

वरदान या अभिशाप? एनईपी 2024 की वास्तविकता को डिकोड करना

विजय गर्ग

एनईपी 2024, एनईपी 2020 का उत्तराधिकारी है, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से पुनर्जीवित करना है। यह ग्री-स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर, ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, उच्च शिक्षा का पुनर्गठन और बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का समावेश शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2024 गहन जांच और बहस का विषय रही है, खासकर भारत में उच्च शिक्षा के लिए इसके निहितार्थ के संबंध में। अधिवक्ता इस क्षेत्र में क्रांति लाने की इसकी क्षमता की सराहना करते हैं, जबकि आलोचक इसकी व्यावहारिकता और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में आपत्ति व्यक्त करते हैं। एनईपी वैश्विक प्रदर्शन और सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। प्रबंधन संस्थान छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय नैकरी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विनिमय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनशिप और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की पेशकश कर सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य एनईपी 2024 के सूक्ष्म पहलुओं पर गौर करना है, इसके फायदे और नुकसान का आकलन करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह उच्च शिक्षा के लिए वरदान है या अभिशाप। एनईपी 2024 को समझना एनईपी 2024, एनईपी 2020 का उत्तराधिकारी है, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से पुनर्जीवित करना है। यह ग्री-स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर, ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, उच्च शिक्षा का पुनर्गठन और बेहतर शिक्षण



प्रकाश डालना: शिक्षा में महत्वपूर्ण असमानताएँ हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों और जनसांख्यिकीय समूहों में। एनईपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है कि सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर देता है। यह भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसका जश्न मनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सभी छात्रों के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक है। शिक्षक प्रशिक्षण और विकास पर जोर: शिक्षकों को नई पद्धतियों के साथ सरोखित करने के लिए निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने का प्रयास करती है। 21वीं सदी के लिए प्रासंगिकता: भारत में मौजूदा शिक्षा प्रणाली की अक्सर पुरानी होने और रटने पर केंद्रित होने के कारण असम्यक्ता की जाती है। एनईपी शिक्षा को अधिक प्रामाण्य, लचीला और अंतःविषय बनाने और छात्रों को 21वीं सदी के कार्यबल की मांगों के लिए तैयार करने का प्रयास करती है। समानता और समावेशन के महत्व पर

हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में लगभग 65% प्रतिशत छात्र निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत आवश्यक वित्तीय संसाधन और नवाचार लाती है। इसलिए, सरकार और नियामक निकायों के लिए व्यावहारिक संस्थागत तंत्र बनाना जरूरी है जो निजी क्षेत्र के योगदान का उपयोग करेगा और उन्हें एनईपी प्रक्रिया में समान भागीदार के रूप में मान्यता देगा। एनईपी 2024 के संभावित नुकसान कार्यान्वयन चुनौतियाँ: जबकि एनईपी 2024 उच्च शिक्षा सुधार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, इसका सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। बुनियादी ढांचे की सीमाओं से लेकर नौकरशाही बाधाओं तक, नीति निर्देशकों को कार्रवाई योग्य रणनीतियों में अनुवाद करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे व्यवहार में हासिल करना मुश्किल हो सकता है। एनईपी 2024 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार और 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए अपने युवाओं को तैयार करने की दिशा में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सफलता प्रभावी

कार्यान्वयन और संभावित चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है। सबसे बड़ी चुनौती कार्यान्वयन बाधाओं को दूर करना, डिजिटल विभाजन को पाटना, मूल्यांकन प्रथाओं की पुनर्कल्पना करना और शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ सुरक्षा करना है। मानकीकृत परीक्षण दुविधा: मूल्यांकन के लिए समग्र दृष्टिकोण की वकालत करने के बावजूद, एनईपी 2024 अकादमिक प्रदर्शन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में मानकीकृत परीक्षण पर निर्भरता बरकरार रखता है। आलोचकों का तर्क है कि यह छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों और सीखने की शैलियों की उपेक्षा करते हुए रटकर याद करने और परीक्षा-केंद्रित सीखने को संस्कृति को कायम रखता है। विशाल कार्य: सबसे पहले, भारत के शिक्षा क्षेत्र का विशाल आकार और विविधता कार्यान्वयन को एक कठिन कार्य बनाती है। उदाहरण के लिए, आइए अकेले स्कूली शिक्षा प्रणाली के आकार पर विचार करें। 15 लाख से अधिक स्कूलों, 25 करोड़ छात्रों और 89 लाख शिक्षकों के साथ, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बनी हुई है। उच्च शिक्षा प्रणाली का आकार भी विशाल है। AISHE 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1,000 विश्वविद्यालयों, 39,931 कॉलेजों और 10,725 स्टैंड-अलोन संस्थानों में 3.74 करोड़ छात्र शामिल हैं। इस प्रकार, इस मैग्नी शिक्षा नीति का देशव्यापी कार्यान्वयन एक विशाल अभ्यास और ब्लॉक स्तर पर कई हितधारक शामिल होंगे। नामांकन लक्ष्य हासिल करने में चुनौती: श्रृंख नीति का लक्ष्य 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करना है, इसके लिए हर महीने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण की आवश्यकता होती है। अगले 15 वर्षों के लिए k, जो एक बड़ी चुनौती है। शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण का अभाव: उन्नत पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए, भारत को

सक्षम शिक्षकों के एक बड़े समूह की आवश्यकता है जो नए शैक्षणिक दृष्टिकोण से परिचित हों। चूंकि शिक्षक आम तौर पर एक अनुशासनात्मक एंकरिंग संस्कृति साझा करते हैं, इसलिए असाधारण कौशल वाले ऐसे शिक्षकों का होना मुश्किल है जो एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हों और साथ ही अन्य विषयों में भी रुचि रखते हों। अपर्याप्त फंडिंग: प्रमुख पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए दशकों तक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। एकाधिक प्रवेश और निकास: एनईपी में बड़ी छात्र आबादी के कारण भारत में एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे उच्च शिक्षा में उच्च वार्षिक प्रवेश प्राप्त हो सकता है। विश्वविद्यालयों के लिए यह अनुमान लगाया मुश्किल हो सकता है कि कितने छात्र इसमें शामिल होंगे और बाहर निकलेंगे और सरकार को हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री जैसे विभिन्न स्तर के कार्यक्रमों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देकर, और उन्नत सीखने के अनुभवों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, एनईपी 2024 में भारत में शिक्षा के भविष्य को आकार देने में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनने की क्षमता है। हालाँकि, इसके संभावित नुकसानों पर सावधानीपूर्वक विचार करना और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि यह वास्तव में एक उज्ज्वल, अधिक न्यायसंगत शैक्षिक परिदृश्य के अपने वादे को पूरा करता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक रत्न भूपार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब -

- :सौजन्य :-

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



टोयोटा किरलोस्कर ने महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक कार प्लांट के लिए 827 एकड़ जमीन की हासिल



परिवहन विशेष न्यूज

टोयोटा किरलोस्कर मोटर को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के लिए समर्पित एक नई विनिर्माण सुविधा के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 827 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। 31 जुलाई को टोयोटा किरलोस्कर मोटर और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नया ग्रीनफील्ड प्लांट महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड परियोजना के तहत केंद्र और महाराष्ट्र सरकारों के बीच एक संयुक्त पहल के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट दिल्ली-मुंबई औद्योगिक

गलियारे (डीएमआईसी) के बिडकिन नोड में स्थित होगा। इस स्मार्ट औद्योगिक शहर का लक्ष्य महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करना है, और टोयोटा किरलोस्कर इस परियोजना में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा, और जनवरी 2026 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

आधिकारिक बयान के अनुसार इस संयंत्र में सालाना 4 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन बनाए जाने की उम्मीद है, जिससे 8,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 18,000 अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार

सृजित होंगे। इस कदम को भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह परियोजना मोटर वाहन क्षेत्र में बदलाव लाएगी तथा वैश्विक ईवी बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

टोयोटा किरलोस्कर की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, नया संयंत्र टिकाऊ विनिर्माण में योगदान देगा तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

पियाजियो और श्रीराम फाइनैस ने 3 व्हीलर फाइनेंसिंग के लिए मिलाया हाथ

परिवहन विशेष न्यूज

इटली के पियाजियो समूह की सहायक कंपनी और भारत के छोटे वाणिज्यिक वाहन बाजार में एक खिलाड़ी पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड (पीवीपीएल) ने भारत भर में तिपहिया वित्तपोषण को और अधिक सुलभ बनाने के लिए श्रीराम फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। पियाजियो में सीबी डोमेस्टिक बिजनेस और रिटेल फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष अमित सागर और श्रीराम फाइनेंस के संयुक्त प्रबंध निदेशक जीएम गिलानी की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस साझेदारी के तहत श्रीराम फाइनेंस पियाजियो के यात्री और कार्गो 3 व्हीलर के लिए कम डाउन पेमेंट, विशेष सौदे और आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करते हुए, विशेष वित्तपोषण विकल्प प्रदान करेगा। यह पहल महिला उद्यमियों का भी समर्थन करेगी, जो अपने वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय को शुरू करने का लक्ष्य रखने वालों के लिए आसान वित्त विकल्प प्रदान करेगी।

इस सहयोग की एक प्रमुख विशेषता स्थायी पते के प्रमाण की कमी वाले उद्यमियों के लिए सरलीकृत ऋण प्रक्रिया है, जो अक्सर शहरों या गांवों के बीच जाने वालों के लिए एक चुनौती होती है। साझेदारी चार साल तक की लचीली ऋण अवधि और ₹20,000-₹25,000 से शुरू होने वाले कम डाउन पेमेंट की पेशकश करती है, जिसका उद्देश्य



3W स्वाचिंत को और अधिक किफायती बनाना है।

अमित सागर ने इस साझेदारी के बारे में आशा व्यक्त की, तथा छोटे वाणिज्यिक वाहन खंड में वित्तपोषण की कमी को पूरा

करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “श्रीराम फाइनेंस के साथ यह साझेदारी अधिक ग्राहकों को वित्तीय बाधाओं के बिना पियाजियो आप वाहन खरीदने में सक्षम बनाएगी।”

जीएम गिलानी ने इस भावना को दोहराते हुए कहा, रपियाजियो के विश्वसनीय ब्रांड और हमारे अभिनव वित्त विकल्पों के साथ, हम 3W को और भी अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

बिहार के उद्यमी की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी के संस्थापक ने क्यों कहा बिहार को 'निराशा की भूमि', बिहार में स्टार्टअप शुरू करना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला'



परिवहन विशेष न्यूज

सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ चंदन राज ने बिहार में कारोबार करने के अपने कठोर अनुभव को साझा करते हुए इसे अपने जीवन का सबसे बुरा फैसला बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रबिहार - हताशा की भूमि। सेमीकंडक्टर/वीएलएसआई कंपनी के रूप में यहां जीवित रहने के लिए बहुत सारी समस्याएं और संघर्ष हैं।”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेमीकंडक्टर की कंपनी के फाउंडर की पोस्ट काफी वायरल हो रही है। इसमें कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। न सड़क है और न स्ट्रीट लाइट। साथ ही वहां और भी कई समस्याएं हैं। इस कारण उन्होंने कई क्लाइंट छो दिए क्योंकि उन क्लाइंट ने इन समस्याओं के चलते उनकी कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था।

चंदन राज ने बिहार की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड शुरू की थी। वह इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। वह अपनी पोस्ट में बताते हैं जहां उनकी कंपनी है, उस जगह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। न सड़क है और न स्ट्रीट लाइट। साथ ही वहां और भी कई समस्याएं हैं। इस कारण उन्होंने कई क्लाइंट छो दिए क्योंकि उन क्लाइंट ने इन समस्याओं के चलते उनकी कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था।

चंदन का जहां ऑफिस है, वह रास्ता काफी खराब है। उनकी पोस्ट पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वह काफी लोगों को जवाब भी दे रहे हैं। चंदन ने बिहार को 'निराशा की भूमि' बताया है। उन्होंने लिखा कि सेमीकंडक्टर/वीएलएसआई कंपनी के रूप में यहां जिंदा रहने के लिए बहुत सारी समस्याएं और संघर्ष हैं।

उन्होंने लिखा है कि वे पिछले चार साल से सड़क और बुनियादी ढांचे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने लिखा है, 'मुझे लगता है कि बिहार सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को नहीं समझती है।’

आईआईटी के पूर्व छात्र आशुतोष नंदन ने सोशल मीडिया पर पिपसेमी के मुखाश्लय की एक तस्वीर साझा



की, जिसमें बताया गया कि राज दो साल से बुनियादी ढांचे में सुधार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। नंदन ने पूछा, रब्या बिहार सरकार इतनी अक्षम हो गई है कि वह सड़क और स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगावा सकती?”

यह भावना अकेली नहीं है। बिहार लगातार व्यापार करने में आसान की लिए राष्ट्रीय रैंकिंग में पिछड़ रहा है, 2022 में राज्यों में 26वें स्थान पर है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी देश में सबसे कम है। जबकि भारत ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, बिहार की औद्योगिक रैंकिंग निराशाजनक रूप से कम है, जो बुनियादी ढाँचे की कमी और नौकरशाही की अक्षमताओं से बाधित है।

एक यूजर के कमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए चंदन ने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो उन्होंने बुनियादी सुविधाओं को सही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा था। इस ईमेल में उन्होंने लिखा है, 'उनके क्षेत्र में सही ढंग की सड़क नहीं है। पंचायत से जुड़े अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैंने रास्ते को मिट्टी से भर दिया था, लेकिन बारिश में यह मिट्टी बह गई।' चंदन ने ईमेल में लिखा है कि वह अपनी समस्या लेकर लगभग हर सरकारी ऑफिस गए। नेताओं के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने लिखा कि काम के बदले उनसे पैसा मांगा जाता है। उन्होंने लिखा कि बिहार में कारोबार करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है।

चंदन की यह पोस्ट वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का जवाब आया। इसमें लिखा है कि उनके ऑफिस के रास्ते का निर्माण दशहरा के बाद शुरू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, 'मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त पथ के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है। दशहरा के तुरंत बाद उक्त पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।' इस पोस्ट के बाद चंदन ने जिला प्रशासन का धन्यवाद दिया।

न्यूगे ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवी बस यात्रा की शुरु

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रीनसेल मोबिलिटी की ओर से भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक बस ब्रांड न्यूगे ने ऐतिहासिक कश्मीर से कन्याकुमारी (ई-के2के) इलेक्ट्रिक बस अभियान की शुरुआत की है। यह महाकाव्य यात्रा भारत में संभारणीय जन गतिशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण छलंग है। इस अभियान के साथ न्यूगे इस तरह की रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला ईवी बस ब्रांड बनने के लिए तैयार है। न्यूगे का लक्ष्य समुद्र तल से 3,500 फीट ऊपर से समुद्र तल तक 4,000+ किलोमीटर की दूरी तय करना है।

बस 200 से ज्यादा शहरों और कस्बों से गुजरते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगी और साथ ही स्थिरता का संदेश भी फैलाएगी। ई-के2के बस अपनी पूरी यात्रा में कई सार्थक गतिविधियों में भाग लेकर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जैसे कि छात्र कार्यशालाएँ, वृक्षारोपण अभियान, सफाई पहल, सुरक्षा-थीम वाले नुक़ड नाटक और रास्ते में कई और प्रभावशाली कार्यक्रम - जो वास्तव में रई-बस जो अच्छा करती है की भावना को मूर्त रूप देते हैं।

न्यूगे की ई-के2के इलेक्ट्रिक बस के पश्चिमी चरण को भारत सरकार के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन



गडकरी ने नागपुर से हरी झंडी दिखाई।

माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा, रमुझे खुशी है कि न्यूगे ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ऐतिहासिक इलेक्ट्रिक बस यात्रा शुरू की है, जो इलेक्ट्रिक मास मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 4,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है और छात्रों और समुदायों के साथ विभिन्न प्रभावशाली गतिविधियों का आयोजन भी करती है, क्योंकि यह 200 से अधिक कस्बों और शहरों से होकर गुजरती है। इलेक्ट्रिक बसें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन

अपनाने का पुरजोर समर्थन किया है। न्यूगे की ई-के2के यात्रा देश के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण सुधारों और लंबी दूरी की यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक बसों की व्यवहार्यता का प्रमाण है। यह पहल भारत की नवाचार और हरित प्रौद्योगिकी के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।”

ग्रीनसेल मोबिलिटी के सीईओ और एमडी श्री देवेन्द्र चावला ने भी भारत में ग्रीन मास मोबिलिटी समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया। “न्यूगे की महत्वाकांक्षी ई-के2के यात्रा हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करवाएगी, जो विभिन्न इलाकों में इलेक्ट्रिक बसों की लचीलापन का प्रदर्शन

करेगी। यह अभियान सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि से कहीं अधिक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 1200 से ज्यादा शहरों और कस्बों से गुजरते हुए, यात्रा का उद्देश्य यात्रा के स्वच्छ तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ईवी बसों में बदलाव के लिए प्रेरित करना है। विभिन्न प्रभावशाली गतिविधियों में शामिल होकर ई-के2के बस वास्तव में ई-बस की भावना को मूर्त रूप देती है जो अच्छा करती है।”

यह यात्रा 4 अक्टूबर को जम्मू से शुरू हुई थी। खूबसूरत घाटियों से लेकर चहल-पहल वाले शहरों तक इस अभियान को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही अलग-अलग इलाकों में इलेक्ट्रिक बसों की व्यवहार्यता का प्रदर्शन भी किया गया है। जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, न्यूगे की इलेक्ट्रिक बसें भारत भर के समुदायों को प्रेरित करती रहेंगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लाभों और लोगों और ग्रह के लिए स्वच्छ परिवहन समाधानों को अपनाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएगी।

न्यूगे इलेक्ट्रिक बसें सुरक्षा और आराम के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जो मेहमानों को एक बेहतरीन यात्रा अनुभव प्रदान करती हैं, और साथ ही पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती हैं।

दशहरा-दिवाली पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर के कारण हो सकता है नुकसान, गाड़ी खरीदते समय रखें कुछ बातों का ध्यान

भारत में हर साल दिवाली, दशहरा नवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री की जाती है। लेकिन कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियों कर देते हैं जिनके कारण बाद में परेशानी होती है।

Festive Season के दौरान गाड़ी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में हर साल नवरात्र, दशहरा और दीवाली के मौके पर लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री की जाती है। कई बार लोग ऑफर्स के कारण गाड़ी खरीदने में कुछ गलतियां कर देते हैं और बाद में उनको परेशानी होती है। Festive Season के दौरान नई गाड़ी खरीदते समय किस तरह की गलतियों को करने से बचना (Car Buying Tips) चाहिए। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। ऑफर्स से न हो प्रभावित



फेस्टिव सीजन के दौरान लगभग हर कंपनी की ओर से अपने वाहनों पर Discount Offers दिए जाते हैं। जिस कारण गाड़ी को खरीदना काफी आसान और सस्ता लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही ऑफर्स के कारण गाड़ी को खरीद लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। इसलिए कभी भी वाहन निर्माताओं की ओर से दिए जाने वाले डिस्काउंट ऑफर्स से प्रभावित होकर गाड़ी न खरीदें।

कम मांग वाले मॉडल पर ज्यादा डिस्काउंट

आमतौर पर कंपनियों की ओर से ऐसे उत्पादों पर ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। जिनकी बिक्री सामान्य दिनों में कम रहती है। ज्यादा मांग वाले मॉडल्स की बिक्री तेजी से होती है और इस कारण कम मांग वाले मॉडल्स शोरूम और स्टॉक यार्ड में खड़े रह जाते हैं। जिस कारण डीलर्स की परेशानी भी बढ़ जाती

है। इसलिए कम मांग वाले मॉडल्स पर कई बार ज्यादा डिस्काउंट देकर ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जाती है।

कैसे उठा सकते हैं फायदा

अगर आपको भी फेस्टिव सीजन के दौरान नई गाड़ी खरीदनी है तो फिर कुछ समय पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। नई गाड़ी को खरीदने से पहले अपना बजट और जरूरत को समझना चाहिए। इसके बाद गाड़ी का चुनाव करना चाहिए। एक बार बजट, जरूरत और गाड़ी का चुनाव करने के बाद ईएमआई, डाउनपेमेंट की पहले से ही तैयारी कर लेना बेहतर रहता है। इसके बाद अगर आपकी पसंद वाली गाड़ी पर फेस्टिव सीजन के दौरान कंपनियों की ओर से डिस्काउंट ऑफर दिए जाते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं Festive Season के दौरान बिना वॉरंटी पेरियड गाड़ी घर लाने में भी किसी तरह की समस्या नहीं होती।

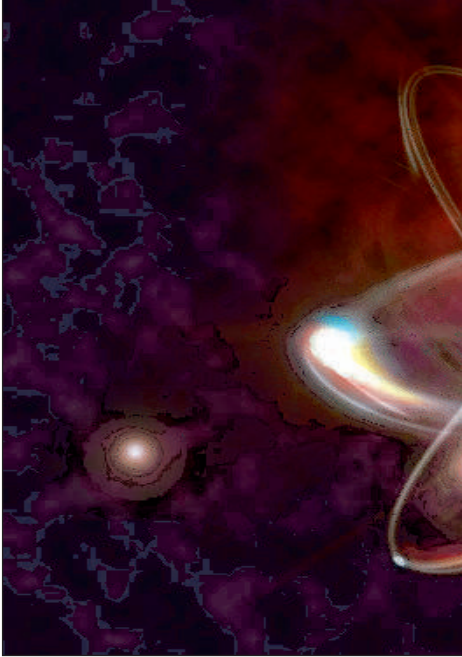


क्वांटम भौतिकी प्रयोग में 'नकारात्मक समय' का प्रमाण मिला



विजय गर्ग

नए अध्ययन के बारे में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में टोरंटो विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी एफ्रैम स्टीनबर्ग ने लिखा, जिसे 5 सितंबर को प्रीप्रिंट सर्वर arXiv.org पर अपलोड किया गया था और अभी तक सहकर्मी-समीक्षा नहीं की गई है। इस काम का विचार 2017 में सामने आया। उस समय, स्टाइनबर्ग और एक प्रयोगशाला सहयोगी, तत्कालीन डॉक्टरेट छात्र जोशिया सिंक्लेयर, प्रकाश और पदार्थ की बातचीत में रुचि रखते थे, विशेष रूप से परमाणु उत्तेजना नामक एक घटना: जब फोटॉन एक माध्यम से गुजरते हैं और मिलते हैं अवशोषित, उस माध्यम में परमाणुओं के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं। जब ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो वे उस अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित फोटॉन के रूप में छोड़ देते हैं, जिससे माध्यम में परमाणु से प्रकाश के देखे गए पारगमन समय में देरी होती है। सिनक्लेयर की टीम उस समय विलंब को मापना चाहती थी (जिसे कभी-कभी तकनीकी रूप से र समूह विलंब कहा जाता है) और यह जानना चाहता था कि क्या यह उस फोटॉन के भाग्य पर निर्भर करता है: क्या यह परमाणु बदल के अंदर बिखरा हुआ और अवशोषित था, या यह बिना किसी बातचीत के प्रसारित हुआ था? सिनक्लेयर कहते हैं, इस समय, हम निश्चित नहीं थे कि उत्तर क्या है, और



हमें लगा कि किसी चीज के बारे में इतना बुनियादी प्रश्न का उत्तर देना आसान होना चाहिए। र लेकिन जितने अधिक लोगों से हमने बात की, उतना ही अधिक हमें एहसास हुआ कि हालांकि हर किसी के पास अपना अंतर्ज्ञान या अनुमान था, लेकिन सही उत्तर क्या होगा, इस पर कोई विशेषज्ञ सहमत नहीं थी। र क्योंकि इन देरी की प्रकृति इतनी अजीब और प्रतिकूल हो सकती है, कुछ शोधकर्ताओं ने प्रकाश से जुड़ी किसी भी भौतिक संपत्ति का वर्णन करने के लिए इस घटना को प्रभावी रूप से अर्थहीन करार दिया था। तीन साल की योजना के बाद, उनकी टीम ने प्रयोगशाला में इस प्रश्न का परीक्षण करने के लिए एक उपकरण विकसित किया। उनके प्रयोगों में अल्ट्राकोल्ड रूबिडियम परमाणुओं के एक बादल के माध्यम से फोटॉन की शूटिंग और परमाणु उत्तेजना की परिणामी डिग्री को मापना शामिल था। प्रयोग से दो आश्चर्य सामने आए: कभी-कभी फोटॉन बिना किसी क्षति के गुजर जाते थे, फिर भी रूबिडियम परमाणु उत्तेजित हो जाते थे - और तब तक जब तक कि उन्होंने उन फोटॉनों को अवशोषित कर लिया हो। अजीब बात है, जब फोटॉन को अवशोषित किया जाता था, तो वे लगभग तुरंत ही उत्सर्जित होते प्रतीत होते थे, रूबिडियम परमाणुओं के अपनी जमीनी स्थिति में लौटने से काफी पहले - जैसे कि फोटॉन, औसतन, परमाणुओं को तेजी से छोड़ रहे थेअर्पित। इसके बाद टीम ने स्पष्टीकरण तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रिफ़िन विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक और क्वांटम भौतिक विज्ञानी हॉवर्ड वाइसमैन के साथ सहयोग किया।

उभरे हुए सैद्धांतिक ढांचे से पता चला कि परमाणु उत्तेजना के रूप में इन संचरित फोटॉनों द्वारा बताया गया समय प्रकाश द्वारा प्राप्त अपेक्षित समूह विलंब के साथ पूरी तरह से मेल खाता है - यहां तक कि उन मामलों के लिए भी जहां ऐसा लगता था कि परमाणु उत्तेजना कम होने से पहले फोटॉनों को फिर से उत्सर्जित किया गया था। निरर्थक खोज को समझने के लिए, आप फोटॉन को फजी क्वांटम ऑब्जेक्ट के रूप में सोच सकते हैं, जिसमें परमाणु उत्तेजना के माध्यम से किसी भी फोटॉन का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन एक निश्चित निश्चित समय पर होने की गारंटी नहीं है, बल्कि, यह लौकिक मूल्यों की एक घिसी-पिटी, संभाव्य सीमा में घटित होता है। जैसा कि टीम के प्रयोगों से पता चला है, ये मान ऐसे उदाहरणों को शामिल कर सकते हैं जब किसी व्यक्तिगत फोटॉन का पारगमन समय तात्कालिक होता है - या, विचित्र रूप से, जब यह परमाणु उत्तेजना समाप्त होने से पहले समाप्त होता है, जो एक नकारात्मक मूल्य देता है। र मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि हम इस भविष्यवाणी से पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे, र सिंक्लेयर कहते हैं, समूह में देरी और प्रेषित फोटॉन द्वारा परमाणु उत्तेजना के रूप में बिताए गए समय के बीच मिलान का जिक्र करते हुए। र और जैसे ही हमें विश्वास हो गया कि हमने कोई गलती नहीं की है, स्टाइनबर्ग और टीम के बाकी सदस्य - मैं इस बिंदु तक मैं साचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी] में पोस्टडॉक करने के लिए आगे बढ़ चुका था - एक अनुसरण करने की योजना बनाना शुरू कर दिया नकारात्मक निवास समय की

इस पागल भविष्यवाणी का परीक्षण करने के लिए - up प्रयोग करें और देखें कि क्या सिद्धांत कायम रहेगा। वह अनुवर्ती प्रयोग, जो एंगुलो के नेतृत्व में था, जिसे स्टाइनबर्ग ने एक्स पर प्रचारित किया था, एक फोटॉन को प्रसारित करने के दो तरीकों पर विचार करके समझा जा सकता है। एक में, फोटॉन विभिन्न प्रकार के ब्लाईंड्स से पहनता है और परमाणु को पूरी तरह से नजर अंदाज कर देता है, यहां तक कि बिना सिर हिलाए भी निकल जाता है। दूसरे में, यह परमाणु के साथ संपर्क करता है, उसे पुनः उत्सर्जित होने से पहले उच्च ऊर्जा स्तर तक बढ़ाता है। र जब आप एक संचरित फोटॉन देखते हैं, तो आप नहीं जान सकते कि इनमें से कौन सा घटित हुआ, र स्टाइनबर्ग कहते हैं, क्योंकि फोटॉन क्वांटम क्षेत्र में क्वांटम कण हैं, दो परिणाम सुपरपोजिशन में हो सकते हैं - दोनों चीजें एक ही समय में हो सकती हैं. र मापने वाला उपकरण शून्य को मापने और कुछ छोटे सकारात्मक मान को मापने की सुपरपोजिशन में समाप्त होता है। र लेकिन इसके अनुरूप, स्टाइनबर्ग कहते हैं, इसका मतलब यह भी है कि कभी-कभी र मापने वाला उपकरण ऐसी स्थिति में समाप्त होता है जो 'शून्य' प्लस 'कुछ सकारात्मक' जैसा नहीं दिखता है, बल्कि 'शून्य' शून्य 'कुछ सकारात्मक' जैसा दिखता है, जिसके परिणामस्वरूप जो दिखता है वह गलत होता है इस उत्तेजना समय के लिए संकेत, एक नकारात्मक मान। र एंगुलो और उनके सहयोगियों के प्रयोग में माप के परिणाम बताते हैं कि जब परमाणु अपनी जमीनी अवस्था में रहते थे, तब की तुलना में जब फोटॉन परमाणुओं को उत्तेजित

करते थे, तो वे माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते थे। (फोटॉन किसी भी जानकारी का संचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए परिणाम आईस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत द्वारा निर्धारित र कोई भी चीज प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकती र गति सीमा का खंडन नहीं करती है।) र एक नकारात्मक समय विलंब विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यदि आपने यह मापने के लिए एक 'क्वांटम' घड़ी बनाई है कि परमाणु उत्तेजित अवस्था में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो घड़ी की सुई, कुछ परिस्थितियों में, आगे की बजाय पीछे की ओर बढ़ेगी, सिंक्लेयर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह समय जिसमें फोटॉन परमाणुओं द्वारा अवशोषित किए गए थे, नकारात्मक है। भले ही यह घटना आश्चर्यजनक है, इसका समय की हमारी समझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है - लेकिन यह एक बार फिर स्पष्ट करता है कि क्वांटम दुनिया अभी भी मेरे पास भंडार में आश्चर्य है। "[अंगुलो] और बाकी टीम ने वास्तव में कुछ प्रभावशाली हासिल किया है और माप का एक सुंदर सेट तैयार किया है। उनके नतीजे अवशोषण मीडिया के माध्यम से यात्रा करने वाले फोटॉन के इतिहास के बारे में दिलचस्प सवाल उठाते हैं और प्रकाशिकी में समूह देरी के भौतिक अर्थ की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता होती है, रसिनक्लेयर कहते हैं। इस लेख का एक संस्करण मूल रूप से स्पेक्ट्रम डेर विसनशाफ्ट में प्रकाशित हुआ था और अनुमति के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया था। अधिकार एवं अनुमति हैं नैनन बिशोफ एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और साइटिफिक अमेरिकन के भागीदार प्रकाशन स्पेक्ट्रम के संपादक हैं। नैनन बिस्वोर्फ द्वारा और अधिक जेना ब्रायनर साइटिफिक अमेरिकन की प्रबंध संपादक हैं। पहले वह लाइव साइंस की प्रधान संपादक थीं और उससे पहले, स्कोलास्टिक्स साइंस वर्ल्ड पत्रिका की संपादक थीं। ब्रायनर के पास सैलिसबरी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी की डिग्री, मेरीलैंड विश्वविद्यालय से जैव-भू-रसायन और पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान पत्रकारिता की डिग्री है। उन्होंने प्लसिडो में एक जीवविज्ञानी के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने आईडीएम की नियामकी की और भव्य फ्लोरीडा स्कूब जे सहित लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया। उन्हें वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन से समुद्री विज्ञान पत्रकारिता फ़ेलोशिप भी प्राप्त हुई। उनका दृढ़ विश्वास है कि विज्ञान सभी के लिए है और लगभग हर चीज को विज्ञान के चरम से देखा जा सकता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब मोबाइल नंबर 9465682110

राय

आकांक्षाओं के बोझ तले दबते युवा

इन दिनों विद्यार्थियों के बीच आत्महत्या की खबरें बढ़ रही हैं। पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या करने वालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में विफल होने के अलावा, आइआईटी में पढ़ने वाले और 'नीट' पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भी शामिल हैं। तो क्या प्रतियोगी परीक्षा पास करने से खुश होने की जगह तनाव से छात्र प्रेरान हैं?

दिल्ली से लेकर कानपुर और कोटा तक कोचिंग का बाजार फैल चुका है। अब कोचिंग संस्थान छात्रों को अपने 'लोगो' वाला बैग और टी-शर्ट भी पहना रहे हैं। इनमें ज्यादा संख्या उन छात्रों की है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग से अलग कुछ करना चाहते थे, लेकिन माता-पिता के दबाव में डाक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर बन कर और सरकारी नौकरी के भंवर जाल में घूम रहे हैं। स्कूल से लेकर कोचिंग तक सिमटी दिनचर्या में बच्चों के पास अपनी प्रतिभा पहचानने का मौका नहीं है, बस 'टेस्ट' की तैयारी का दबाव है। क्या अभिभावक कभी रुक कर सोचते हैं कि बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि वह इय रास्ते चलना चाहता है या नहीं? होता यह है कि बड़ी संख्या में गांवों से शहर आए अभिभावक, अपने अतीत के चरम से बच्चों का भविष्य देखने की आशंका करते हैं। ऐसे में अनजाने ही बच्चे, उनको अपना सपना पूरा करने का साधन दिखते हैं।

अगर मां-बाप अपनी अधूरी ख्वाहिशें बच्चों पर लादने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चों में एक असमंजस बना रहता है कि वह अपने मन का काम करें या माता-पिता का कहा मानें? इस तरह उनकी अपनी प्रतिभा दब जाती है और वे भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। विफलता का हल्का झटका भी उन्हें गंभीर तनाव की स्थिति में ला देता है। अभिभावकों को आइए खना चाहिए कि 2019-2023 3 के बीच आठ हजार से अधिक छात्रों ने आइआईटी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, आइआईएम में भी आठ सौ से अधिक छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और संस्थान छोड़ दिया। वैसे, छात्र तनाव की जिंदगी जीने के बजाय अपनी पसंद का रचनात्मक कार्य करें और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, तो अभिभावकों को खुश होना चाहिए।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में तेरह हजार से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। यानी हर महीने एक हजार से अधिक ने ने मृत्यु का वरण किया। जिस देश में मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए गलफाट प्रतियोगिता हो, वहां आखिर क्यों पिछले पांच वर्षों में 119 मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या कर ली? अगर किसी उत्कृष्ट संस्थान में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता में उतीर्ण होना ही जीवन में खुशहाली का पैमाना है, तो फिर आइआईटी, एनआईटी और आइआईएम से भी आत्महत्या तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की खबरें क्यों आ रही हैं? देश में आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों में लड़के-लड़कियां दोनों शामिल हैं। इसमें भी लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। 2019 के आंकड़े देखें, तो उस वर्ष दस हजार से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की थी, जिसमें लगभग चौवन फीसद लड़के और छियालीस फीसद लड़कियां थीं। देश में छात्रों के बीच आत्महत्या की दर पांच वर्ष में पैंतीस फीसद से अधिक बढ़ी है। क्या इन संकेतों से अभिभावक और समाज कोई सबक सीख रहे हैं? क्या छात्रों के जीवन में स्कूल, कोचिंग, घर के अलावा खेलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए समय मिल रहा है?

अभिभावकों के दबाव के साथ-साथ सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने की परीक्षा के चलते छात्र अपनी पसंद का व्यवसाय और पढ़ाई नहीं चुन पाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें लगने लगता है कि वे जो कार्य कर रहे हैं, वास्तव में उससे उछरी नहीं मिल रही है। कोरोना के बाद दुनिया भर में लोगों ने अपनी नियमित नौकरी छोड़ दी और अपनी पसंद का काम शुरू किया। जर्मनी, अमेरिका और जापान के साथ भा में भी 'फ्लेक्सिबल वर्किंग' का चलन शुरू हुआ है।

विजय गर्ग

कई देश विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण, अनुसंधान के अवसर और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां महत्वाकांक्षी डॉक्टरों के लिए कुछ सर्वोत्तम देश दिए गए हैं: चिकित्सा शिक्षा भारत और दक्षिण एशिया के छात्रों के लिए अत्यधिक मांग वाला क्षेत्र है, और शैक्षिक गुणवत्ता और कैरियर की संभावनाओं दोनों के लिए सही गंतव्य का चयन कर के रूप में महत्वपूर्ण है। भारत में, 24 लाख से अधिक छात्र NEET के माध्यम से सिर्फ 1 लाख एमबीबीएस सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस तीव्र प्रतिस्पर्धा ने कई लोगों को अंतर्राष्ट्रीय विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है। ऐतिहासिक रूप से, यूके एक पसंदीदा विकल्प था, लेकिन हाल के वर्षों में, अन्य देश चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरे हैं। एक चिकित्सा गंतव्य के रूप में ब्रिटेन का पतन आजादी से पहले, यूके भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य था। हालाँकि, भारत की आजादी से पहले, यूके मेडिकल छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य था। हालाँकि, 1970 के दशक के अंत में ब्रिटेन द्वारा भारतीय मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देना बंद करने के बाद, रुचि कम हो गई और छात्रों ने रूस जैसे अन्यत्र देखना शुरू कर दिया। रूस की लोकप्रियता के बावजूद, भाषा बाधा और रूसी-माध्यम कार्यक्रमों की व्यापकता ने

भारतीय छात्रों के लिए अनुकूलन को कठिन बना दिया, जिससे कई लोगों को अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ी। मेडिकल हब के रूप में चीन का उदय 2000 के दशक के लिए प्रसिद्ध हैं। चीन ने अपने मजबूत बुनियादी ढांचे, फिनायती द्यूशन और प्रासंगिक पाठ्यक्रम के कारण प्रमुखता हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी माध्यम के कार्यक्रम शुरू किए गए। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के बाद यात्रा प्रतिबंधों और नए भारतीय नियमों ने बाधाएँ पैदा की हैं, क्योंकि चीन वर्तमान में अंग्रेजी में लाइसेंसिंग परीक्षा की पेशकश नहीं करता है, जिससे भारतीय छात्रों के लिए वापसी का मार्ग जटिल हो गया है। फिलीपींस एक लोकप्रिय विकल्प फिलीपींस अपने अंग्रेजी-आधारित पाठ्यक्रम और भारत की विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (एफएमजीई) में उच्च सफलता दर के कारण एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। यह भारत में चिकित्सा अभ्यास में सहज परिवर्तन चाहने वाले छात्रों के लिए इसे एक मजबूत विकल्प बनाता है। हालाँकि, क्लिनिकल एक्सपोजर क्षेत्र और मेडिकल स्कूल के आधार पर भिन्न हो सकता है, कुछ स्कूलों में उन्नत सुविधाओं तक सीमित पहुँच होती है। नेपाल और बांग्लादेश: निकट और



सुविधाजनक घर के करीब होने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए, नेपाल और बांग्लादेश अंग्रेजी में फिनायती चिकित्सा कार्यक्रम पेश करते हैं, जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक समानताएं उन्हें आकर्षक बनाती हैं। कम यात्रा दूरी छात्रों के लिए सुविधा बढ़ाती है। हालाँकि, नेपाल में चुनौतियों में स्थानीय भाषा सीखना और इंटरनशिप के दौरान रोगी की सीमित देखभाल शामिल है। बांग्लादेश में, भीड़भाड़ वाले मेडिकल स्कूल सीखने के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं, और कुछ क्षेत्रों में कभी-कभार राजनीतिक अशांति के साथ-

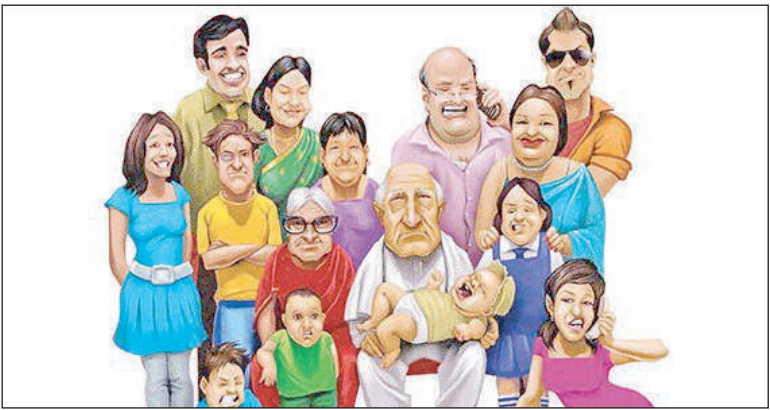
साथ रहने की स्थिति भी निम्न स्तर की होती है। कैरिबियन: एक बढ़ता हुआ विकल्प अमेरिका में उच्च प्रतिस्पर्धा या फीस से डरे हुए लोगों के लिए कैरिबियाई मेडिकल स्कूल तेजी से आकर्षक होते जा रहे हैं। ये संस्थान यूएस-आधारित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, जिससे छात्रों को यूएस, यूके और कनाडा के प्रतिष्ठित शिक्षण अस्पतालों में क्लिनिकल रोटेशन तक पहुँच प्राप्त होती है। यह एक्सपोजर विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के भीतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है, जिससे उनका चिकित्सा प्रशिक्षण समृद्ध होता है।

कैरिबियाई मेडिकल स्कूल छोटे वर्ग के आकार की पेशकश करते हैं, व्यक्तिगत ध्यान और बेहतर छात्र-संकाय बातचीत को बढ़ावा देते हैं। कई स्कूल समर्पित यूएसएमएलई तैयारी प्रदान करते हैं, जिससे लाइसेंसिंग परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी बढ़ती है। स्नातक अक्सर मजबूत अमेरिकी रेजीडेंसी प्लेसमेंट का आनंद लेते हैंअवसर, उनके करियर की संभावनाओं को बढ़ावा। किफायती द्यूशन, सीधे प्रवेश और कई वार्षिक प्रवेश के साथ, यूके शिक्षण अमेरिका में अभ्यास करने के इच्छुक चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। हालाँकि, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त और अच्छी तरह से स्थापित स्कूलों पर शोध करना चाहिए। अन्य उभरते गंतव्य जॉर्जिया और किरिगस्तान जैसे देशों में भी अपने अंग्रेजी-माध्यम कार्यक्रमों और फिनायती द्यूशन के कारण लोकप्रियता हासिल की है। हालाँकि, छात्रों को प्रतिबद्ध होने से पहले इन क्षेत्रों की भू-राजनीतिक स्थिरता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा के लिए सही देश चुनना किसी भी इच्छुक डॉक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रत्येक देश अद्वितीय लाभ प्रदान करता है, और छात्रों को अपनी पसंद बनाने से पहले कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।

घर आंगन सब सूने

इस पीढ़ी के लिए कोई नई बात नहीं है। सभी तरह की सीमाएं टूट रही हैं और घरों की परिभाषा भी अब बदल गई है। महानगरीय जिंदगी में गांव से पलायन ने रोजगार की इस ऊँची उड़ान के साथ-साथ सपनों के नए संसार का भविष्य बनाने के लिए ईसान को अकेला कर दिया है और नई पीढ़ी इसका शिकार और लुभावनेपन में अंतर नहीं कर पा रही है। अब लोगों ने पश्चिमी देशों के साथ-साथ सुदूर आस्ट्रेलिया - न्यूजीलैंड से लेकर मध्य पूर्व और फिलिपींस जैसे देशों में भी जाना शुरू कर दिया है, हालांकि यह भी सही है कि रोजगार के लिए आदमी कहाँ-कहाँ चला जाता है। आज केरल से लेकर पंजाब तक गांवों में पलायन से जिस तरह घर खाली हो रहे हैं, उसमें यह साफ दिखने लगा है कि आज घरों की मुंडेरों पर कौवे - कांव-कांव नहीं बोलते।

संत कबीर ने काफी पहले यह कहा था कि मन-मस्तिष्क में जब सुनापन आ जाए तो फिर प्रभु ही उस पर कृपा करता है। मगर आज यह किसकी कृपा है? आज बदलते हुए हालातों और सपनों को साकार करने की यह एक ऐसी दौड़ है, जिसमें हमने अपना समाज, परिवार, घर, रिश्ते-नाते, दोस्ती और जल, जंगल, जमीन से ही कन्नी काट ली है। हम टूटे वीरान घरों की बात करते हैं, जहाँ अब दरवाजे पर ताले लटक रहे



हैं। कोई डाकिया ऐसे घरों और सुनसान उदास कर देने वाली गलियों में बांटने नहीं आता। ऐसे तमाम घर हैं, जिनमें बचे हुए वृद्ध माँ - बाप खाली गलियों में और चौखट पर खड़े होकर मोबाइल की रोशनी में कभी-कभी वीडियो काल पर अपने बेटे-बेटियों और उनके बच्चों से बात करते हैं। वैराग्य और उदासी का यह आलम आखों के आंसुओं को सोख रहा है और मानवीय त्रासदी के नए अध्याय को भी दुनिया के सामने खोल रहा है कि यह कैसी जिंदगी हमने इस सुनेपन की अवस्था में जीना शुरू कर दिया है। यह किस समाज की निशानी है? हमारे अपने देश की धरती, जिसमें

भारतीयता की संस्कृति में एक अपनेपन की लय है, मन में प्रेम की गंगा बहती है, वहां से लोग तमाम घर हैं, जिनमें बचे हुए वृद्ध माँ - बाप मजबूर होते हैं, पर इस होड़ में पलायन कर गए युवा क्या कभी अपने घर लौट पाएंगे? समंदर के किनारों से आने वाली ठंडी हवा और पांच नदियों से पंजाब का पानी उस विह्व और उदासी को और गहरा कर चुका है जो शायद ही कभी खत्म होगी। यह भी सच है कि आने वाले दो दशकों में पूरे भारत का सामाजिक ताना- बाना जिस तरह से बदल जाएगा, उस तरह से धरती के भूभाग एक अलग पहचान के होंगे, जहां हमारी भाषा, बोलचाल और हमारा चेहरा - मोहरा बदल

जाएगा, क्योंकि सदियों की विरासत से मिली-जुली संस्कृति अब खत्म होती लग रही है। राजनीतिक पार्टियां अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती कि इस राजनीतिक शून्य को किस तरह नापा जाएगा और किस तरह से हम आने वाले दिनों में 'डीफेक' और कृत्रिम बुद्धिमता की अनिवार्यता से बच पाएंगे। समय का सच और समय की नब्ब टटोलते हुए कहा जा सकता है कि इन दिनों जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच गई है, जहां धूप बेगानी है, पानी भी बेगानी है, रूह परदेसी हो गई है और आंखों में पानी सूख गया है, मुंडेरें सूनी हैं, हमारे खेत सूने हो रहे हैं और खाली पड़े आंगन में उगती हुई घास और मृत्यु का सशान दिखता माहौल किस खुशहाला देश की कामना करता है? यह समाज जिस मोड़ पर पहुंच गया है, वहां घर, मकान, आंगन- सब सूने और मन भी सूना है। धरती, घर और मां को छोड़ना कितना मुश्किल है, यह उससे पूछा जा सकता है, जो रहते तो विदेश में हैं, पर आंखों में हर समय भारत धड़कता है और दिल में घर का आंगन हर वक्त कुछ कहता है। दिल की बात भारतीयता की बात है। अभी भी बहुत कुछ नहीं गया है। लोग वापस लौटते हैं और पूरी दुनिया के फलक पर सीखा हुआ अपनी धरती पर दे देते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

